आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 21.02.2026
समय 13;05

मुख्य समाचार:-

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज से शुरू होने वाली उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दी।

आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ मेला-2027 की तैयारियों की समीक्षा के लिए हरिद्वार पहुंचे।

देशभर के दिव्यांगजनों के हुनर को मंच देने के लिए आज से देहरादून में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में परिवहन सुधार के लिए 125 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी।

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बैठक कर राज्य में ड्रैगन फ्रूट, कीवी और सेब उत्पादन समेत फलोत्पादन को बढाने और संबंधित योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की।

बोर्ड परीक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर राज्य में आज से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा जीवन की सफलता की अंतिम कसौटी नहीं, बल्कि आपके उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है इसलिए

सभी शांत मन, एकाग्रचित्त और दृढ़ विश्वास के साथ परीक्षा दें और सफलता प्राप्त करें। राज्य में बोर्ड परीक्षा के लिए एक हजार 261 परीक्षा केंद्र बनाकर 156 संवेदनशील और छः अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इस साल प्रदेशभर में दो लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे।

कुंभ मेला-2027

आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ मेला-2027 की तैयारियों की समीक्षा के लिए हरिद्वार पहुंचे जहां मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 34 प्रमुख अवसंरचना कार्यों का शिलान्यास किया। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 234.55 करोड़ रूपए की लागत के इन स्थाई प्रवृत्ति के कार्यों का उद्देश्य कुंभ मेले के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के साथ ही जिले में के दीर्घकालीन विकास को सुदृढ़ करना है। मुख्यमंत्री द्वारा हरिद्वार के कुम्भ मेला नियंत्रण भवन में मेले की तैयारियों की समीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक ली जा रही है।

दिव्य कला मेला

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देहरादून में आज से "दिव्य कला मेला" का आयोजन किया जा रहा है। रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस नौ दिवसीय मेले में भारत के करीब 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और

उद्यमी प्रतिभाग करेंगे। इस मेले में दिव्यांगजनों की हस्तशिल्पकला और उनके कौशल को मंच मिलेगा। 22 फरवरी को इसका उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा करेंगे।

प्रोत्साहन राशि

भारत सरकार ने उत्तराखंड में परिवहन सुधार के लिए 125 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार से राज्य को पूंजीगत निवेश योजना 2025-26 के तहत 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रोत्साहन राशि को मंजूरी मिलने पर कहा कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परिवहन क्षेत्र में तकनीक आधारित सुधारों को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री धामी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट और वाहन स्क्रैपिंग नीति के लागू करने से प्रदेश में दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ- साथ पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन के माध्यम से ग्रीन सेस की वसूल किया जा रहा है।

फलोत्पादन

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में कल आयोजित हुई बैठक में राज्य में फल उत्पादन को बढ़ावा देने और फलोत्पादन

को आजीविका का सशक्त माध्यम बनाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रदेश को “फल पट्टी” के रूप में विकसित करने की दिशा में ड्रैगन फ्रूट उत्पादन, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के तहत कीवी उत्पादन, सेब की अति सघन बागवानी योजना के साथ ही सेब तुड़ाई क बाद प्रबंधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान श्री बर्धन ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक परिस्थितियां फलोत्पादन के लिए अनुकूल हैं, इसलिए फल प्रजातियों, उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का चयन करते हुए क्लस्टर आधारित और तकनीक समर्थित मॉडल अपनाया जाना चाहिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने 10 क्लस्टरों का विकास करने, फलोत्पादन के लिए 30 प्रोग्रेसिव किसानों को तैयार करने के साथ ही उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण, फील्ड डेमो और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव

राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की प्रगति और उनसे संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। उन्होंने गैस वितरण कंपनियों को गैस पाइपलाइन और सीएनजी स्टेशन स्थापना के लिए चिन्हित स्थलों पर आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कंपनियों को कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने और भूमि आवश्यकताए कार्य अवधिए अनापत्तियों व अन्य लंबित प्रकरणों का समाधान शीघ्र जिला स्तर पर बैठक करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक जिले में जिला पूर्ति अधिकारी को सिटी गैस वितरण कंपनियों के समन्वय के लिए नोडल

अधिकारी नामित करने तथा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक अधिकारी तैनात करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने कंपनियों को भी निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय-सीमा और मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्य के दौरान आमजन को अनावश्यक असुविधा न होने और परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही।

माय स्कीम पोर्टल

प्रदेश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को आमजन तक सरल,सुलभ और त्वरित रूप में पहुंचाने की दिशा में माय स्कीम पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल पर कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई "मेरी योजना" पुस्तकों में प्रकाशित सभी योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराना हैए जिससे पात्र लाभार्थी योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। यह पोर्टल पारदर्शिता, सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके माध्यम से नागरिकों को योजनाओं की पात्रताए लाभए आवेदन प्रक्रिया और संबंधित विभागीय जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त होगी। संबंधित सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने स्तर पर इस पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। साथ ही अधिक से अधिक नागरिकों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। ताकि समन्वय एवं क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा सके।

गोल्फ कार्ट

देहरादून जिला प्रशासन के सतत् प्रयासों के परिणाम स्वरूप पर्यटन नगरी मसूरी को शीघ्र ही 40 अतिरिक्त गोल्फ कार्ट की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही गोल्फ कार्ट को लेकर जिला प्रशासन के साथ इसी महीने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य मसूरी में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के साथ ही पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुगमए सुरक्षित व पर्यावरण-अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराना है।

वन स्टॉप सेंटर

पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने विण विकासखंड स्थित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं और पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र में 181 महिला हेल्पलाइन कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता, गोपनीयता और समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को आपातकालीन सहायता, कानूनी परामर्श, चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग औरअस्थायी आश्रय जैसी समेकित सेवाएं प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए केंद्र की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए और पीड़ित महिलाओं को त्वरित राहत उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड पंजिकाओं, शिकायत रजिस्टर, आगंतुक पंजिका और काउंसलिंग विवरण सहित अन्य अभिलेखों का अवलोकन कर जरूरी निर्देश दिए।